

वैश्विक बैंकिंग गतिविधियाँ

वैश्विक वृद्धि की कमजोरी, सरकारी ऋण संकट के गहराने तथा वित्तीय बाजार के दबाव के चलते वैश्विक बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हुई। जहां अमरीका के बैंक अपने लीवरेज अनुपात में कमी लाने और थोक वित्तपोषण पर निर्भरता को कम करने में सफल हुए वहीं यूरोपीय बैंकों की थोक में वित्तपोषण पर निर्भरता का स्तर ऊंचा बना हुआ है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बैंकिंग क्षेत्र के मूलभूत संकेतक अच्छे थे जो घरेलू निधायन तथा पूंजी के उच्चतर स्तर के चलते हुई उच्चतर अर्थिक वृद्धि और तुलन-पत्रों की अपेक्षाकृत सुदृढ़ता दर्शाते हैं। बासेल III, जी-एसआईएफआई तथा शैडो बैंकिंग जैसे विनियामक मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परंतु कार्यान्वयन की चुनौती बनी हुई है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने प्रभावी समाधान व्यवस्था तथा बेल-इन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में प्रगति की है। यूरोपियन यूनियन तथा यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने निधायन तथा डीलीवरेजिंग संबंधी जोखिमों का समाधान करने के लिए कई उपाय किये हैं, परंतु चिंताएं बनी हुई हैं। दीर्घाविधि में बैंकों को पहले की तुलना में अधिक सक्रियता से लागत प्रबंधन की रणनीति अपनानी होगी और निवेशकों के विश्वास की बहाली की दिशा में कार्य करना होगा।

1. भूमिका

2.1 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को 2011 में तथा 2012 में अब तक भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसके कारणों में वैश्विक वृद्धि की बहाली की कमजोर गति, यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संबंधी संकट का फिर से उभरना तथा वैश्विक बैंकों के लिए निधायन तथा डीलीवरेजिंग का जोखिम बना रहना था। अन्य कारकों के साथ-साथ यूरो क्षेत्र के वर्तमान सरकारी ऋण संकट से उत्पन्न अनिश्चितता, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं को डाउनग्रेड किये जाने, बैंकों की पूंजी में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी चिंताओं के बीच यूरो क्षेत्र के बैंकों के स्थिरता संबंधी मुद्दों ने 2011-12 के अधिकांश भाग में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार तथा बैंकिंग प्रणाली को अस्थिर बनाए रखा।

2.2 वैश्विक क्रेडिट में हुई वृद्धि एक मिश्रित चित्र प्रस्तुत करती है: उभरते बाजारों में जहां क्रेडिट में वृद्धि बरकरार रही वहीं अमरीका में बहाली के कुछ लक्षण दिखाई दिए, परंतु यूरोपीय देशों में क्रेडिट की वृद्धि दर में गिरावट आई। अमरीका तथा कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ, परंतु यूरोपीय देशों के बैंकों में इसमें गिरावट आई। चुनिंदा क्षेत्रों तथा देशों की बैंकिंग की प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि अमरीका की बैंकिंग प्रणाली ने अपने तुलन-पत्रों में सुधार लाने तथा पूंजी को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में

बैंकों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के दुश्चक्र के चलते जोखिम ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। यूरो क्षेत्र के संकट ने यूके की वित्तीय प्रणाली को भी प्रभावित किया है और उसके बैंकों की निधायन की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण ब्याज दरें बढ़ गई हैं तथा यूके की पारिवारिक इकाइयों और कंपनी उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट की उपलब्धता में कमी आई है।

2.3 शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वैश्विक बैंकिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बढ़ रहा है। उभरते तथा विकासशील देशों में चीन के बैंकों ने शीर्ष के 100 बैंकों की रेटिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। वैश्विक नीतिगत सुधारों के मोर्चे पर बासेल नियम के नियम संबंधी ढांचे, प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थाओं (एसआईएफआई), शैडो बैंकिंग, समाधान व्यवस्थाओं तथा बेल-इन प्रक्रिया में कुछ सुधार हुआ है।

वैश्विक वृद्धि काफी कमजोर बनी हुई है

2.4 वर्ष 2011 के अंतिम भाग में यूरो क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचा। पूरे यूरो क्षेत्र में दबाव की स्थिति रही तथा आस-पास की अर्थव्यवस्थाओं में बांड के प्रतिलाभ में वृद्धि हुई क्योंकि निवेशक सरकारी ऋण की चूक के जोखिम के बारे में अधिक चिंतित हो गए थे। इन घटनाक्रमों ने प्रतिकूल तथा बाजार की स्वतः पूर्ति करने

वाली बाजार की धारणा में बदलाव (जिससे कमजोर देशों को बढ़ते प्रतिलाभ (यील्ड) के प्रतिकूल संतुलन का सामना करना पड़ सकता है), घरेलू बैंकों में निधीयन की कमी तथा कमजोर होती अर्थव्यवस्था के जोखिम को नाटकीय रूप से रेखांकित किया है (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर)-अप्रैल 2012)।

2.5 वैश्विक वृद्धि की दर 2010 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2011 में 3.8 प्रतिशत रह गई (चार्ट II.1)। इस धीमी वृद्धि का कारण मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में गिरावट आना था। दूसरी ओर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की दर उच्चतर बनी रही। विभिन्न पूर्वानुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2012 में वैश्विक वृद्धि की दर कमजोर बनी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य-अक्टूबर 2012 का अनुमान है कि वर्ष 2012 में वैश्विक वृद्धि दर घटकर 3.3 प्रतिशत रह जाएगी तथा इसमें भारी गिरावट आने का जोखिम है।

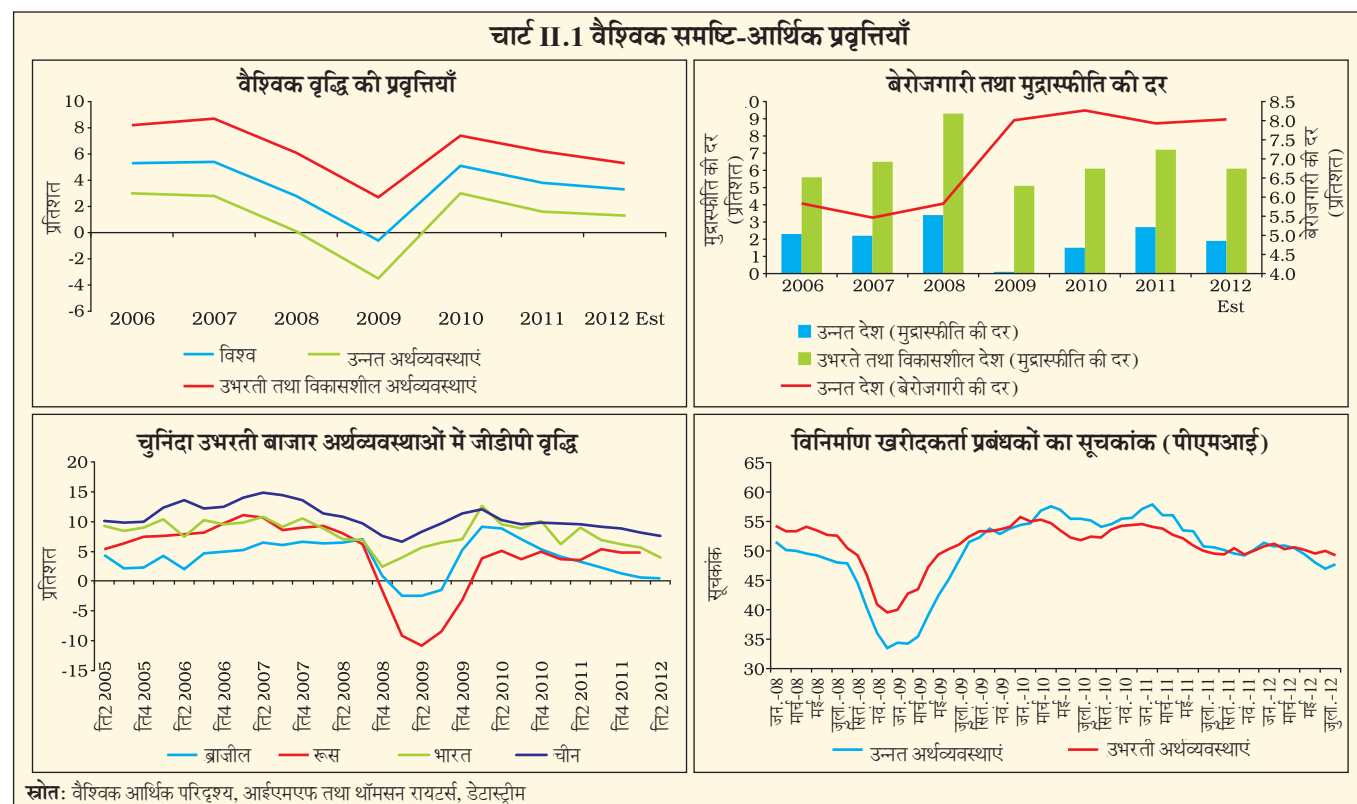
2.6 इस समष्टि आर्थिक परिदृश्य में बैंकिंग कार्यकलापों एवं सुदृढ़ता के संकेतकों का उपयोग करके खंड 2 में वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा की गई है। खंड 3 में कुछ उन्नत तथा उभरती

अर्थव्यवस्थाओं / अर्थव्यवस्था समूहों की बैंकिंग प्रणाली के निष्पादन की विस्तृत चर्चा की गई है। खंड 4 में वैश्विक उपस्थिति में प्रमुख स्थान रखने वाले शीर्ष 100 बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। खंड 5 में वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतिगत उपायों का उल्लेख किया गया है। खंड 6 में वर्ष 2013 के वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के समग्र मूल्यांकन तथा संभावना को प्रस्तुत किया गया है।

2. वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्तियाँ

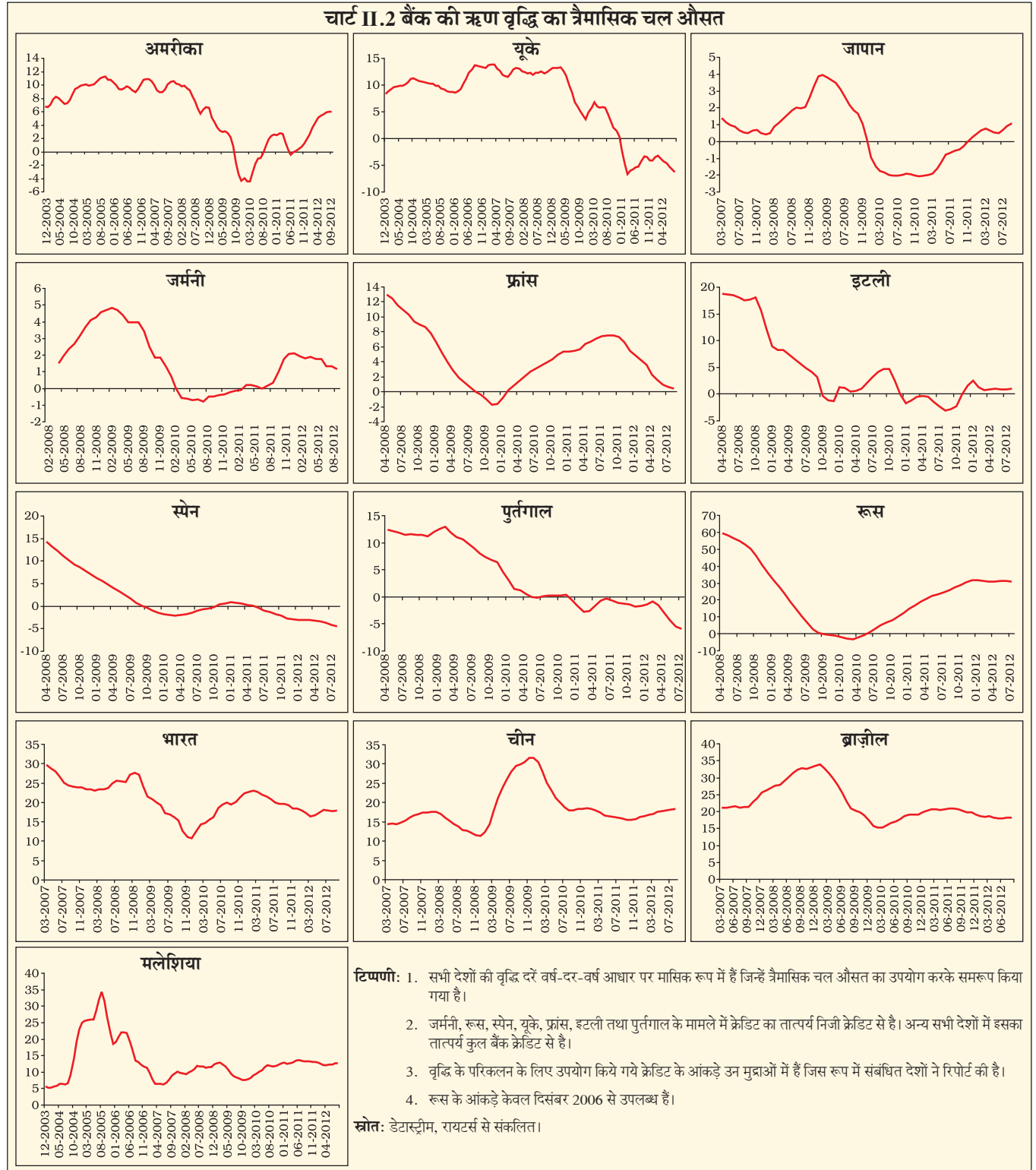
2.7 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट में वैश्विक बैंकिंग उद्योग की कमजोरियों को सामने ला दिया जिसका प्रतिफलन बैंकिंग उद्योग में जनता के घटते विश्वास के रूप में हुआ। हाल के वित्तीय संकट से बैंकिंग क्षेत्र की कमियों का पता चला। बैंक आय के स्थिर तथा विविध स्रोतों को बनाए रखने एवं लागतों में कमी लाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं पर चलनिधि का दबाव बढ़ा। दूसरी बात यह थी कि अपारदर्शी तुलन-पत्रों ने जोखिम के विश्लेषण को काफी हद तक बाधित किया जिसके चलते बैंकों के पूंजी बफर की कमजोरियों के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिल पायी (अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट)।

चार्ट II.1 वैश्विक समष्टि-आर्थिक प्रवृत्तियाँ



विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्रेडिट की वृद्धि दर में भिन्नता

2.8 अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में निष्पादन की भिन्नता के अनुरूप विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में क्रेडिट की वृद्धि दर की प्रवृत्ति में समानता नहीं थी (चार्ट II.2)।



आस्तियों पर प्रतिलाभ गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति दर्शाता है

2.9 आस्तियों पर प्रतिलाभ, जो बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता का एक संकेतक है, में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच भिन्नता देखी गई। सामान्यतः इसकी प्रवृत्ति गिरावट की ओर रही (सारणी II.1)।

वित्तीय दबाव की स्थिति उच्च स्तर पर बनी हुई है

2.10 वर्ष 2011के अंतिम भाग में उन्नत देशों, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के देशों में राजकोषीय घाटे की वहनीयता संबंधी चिंता फिर से उभरकर आई। बाजार द्वारा प्रबल रूप में जोखिम पर ध्यान दिए जाने के चलते यूरो क्षेत्र की प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के सरकारी बांडों के क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप स्प्रेड में बढ़ोतरी हुई। बैंकिंग उद्योग निधीयन संबंधी भारी दबाव में आ गया जैसा कि वैश्विक बैंकों के बढ़ते सीडीएस स्प्रेड से पता चलता है (चार्ट II.3)। उभरती

सारणी II.1: चुनिंदा देशों के बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ

प्रतिशत

देश	2007	2008	2009	2010	2011	2012
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं						
फ्रांस	-	0.1	0.3	0.6	0.4	-
जर्मनी	0.3	-0.1	0.2	0.4	-	-
ग्रीस	1.0	0.2	-0.1	-0.6	-2.1	-
इटली	0.8	0.3	0.3	0.3	-0.9	-
जापान	0.5	0.3	-0.3	0.2	0.3	-
पुर्तगाल	1.1	0.3	0.4	0.5	-0.3	0.1
स्पेन	1.1	0.8	0.6	0.5	0.2	-
यूनाइटेड किंगडम	0.4	-0.4	0.1	0.1	0.1	-
अमरीका	1.2	-0.1	-0.1	0.9	1.2	1.0
उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
रूस	3.0	1.8	0.7	1.9	2.5	-
चीन	0.9	1.0	0.9	1.1	1.3	-
भारत	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
मलेशिया	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6
ब्राजील	3.5	1.6	2.4	3.2	1.5	1.4
मेक्सिको	2.3	1.4	1.5	1.8	1.5	1.8

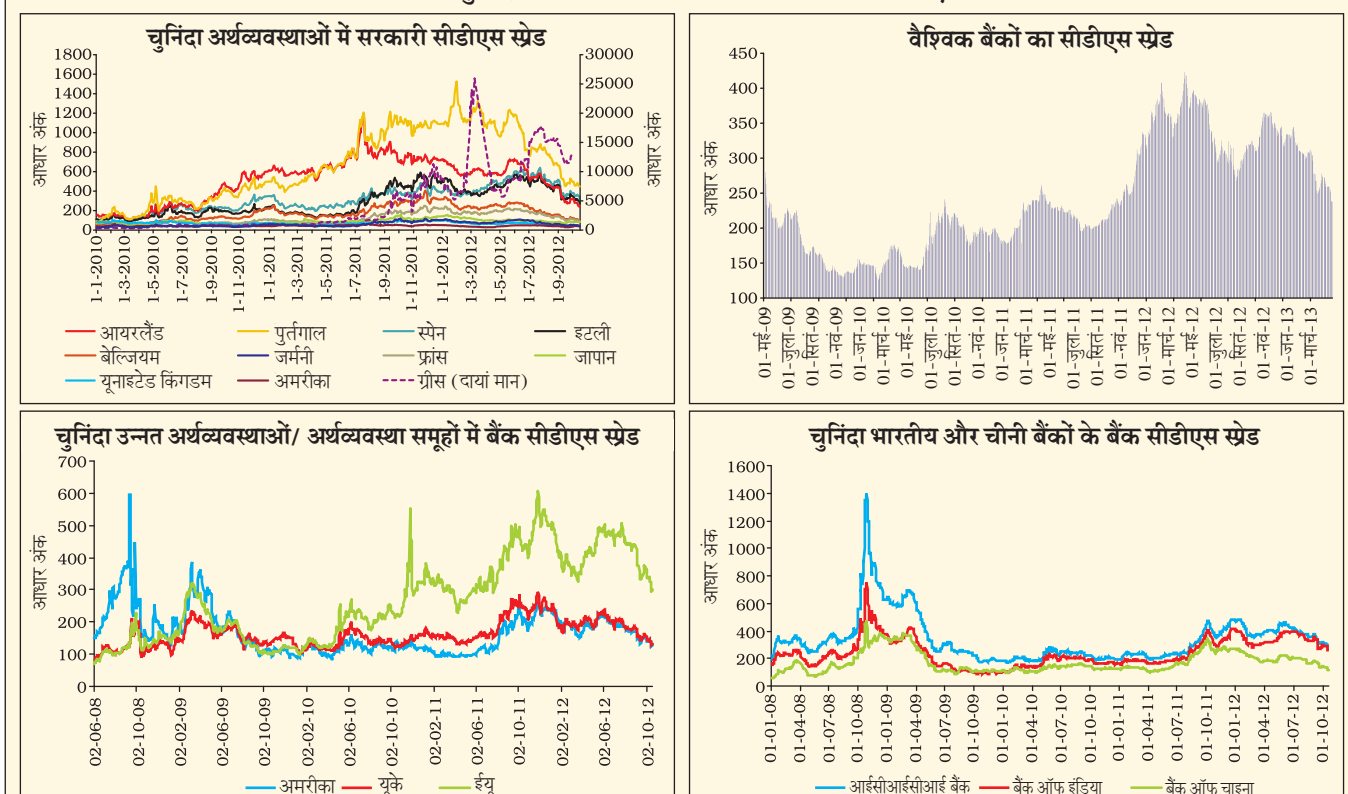
टिप्पणी: - उपलब्ध नहीं

जापान तथा ग्रीस के 2011 के आंकड़े सितंबर के हैं।

पुर्तगाल, अमरीका, भारत, मलेशिया तथा ब्राजील के 2012 के आंकड़े जून के हैं और मेक्सिको के आंकड़े मार्च के हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

चार्ट II.3: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी और बैंक सीडीएस स्प्रेड



टिप्पणी: सरकारी स्प्रेड 5-वर्षीय सीनियर सीडीएस के लिए है जबकि बैंकों का स्प्रेड 5-वर्षीय सीडीएस के लिए है।

स्रोत: सरकारी ऋण तथा वैश्विक बैंकों के सीडीएस स्प्रेड के लिए ब्लूमबर्ग और बैंकों के स्प्रेड के लिए थॉमसन रायटर्स, डेटास्ट्रीम।

बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों में निधायन की स्थिति अपेक्षाकृत अप्रभावित रही क्योंकि निधायन के लिए थोक जमाराशियों पर उनकी निर्भरता सीमित थी।

संक्रमण बैंकों के स्टॉक तक फैला

2.11 बैंकों के स्टॉक, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों के स्टॉक में तेजी से गिरावट आई जो 2011 तथा 2012 के अधिकांश भाग में कुछ देशों के सरकारी ऋण को डाउनग्रेड किए जाने की बात को दर्शाती है (चार्ट II.4)। इसके अलावा कुछ बैंकों पर कथित रूप से धन-शोधन में लिप्त रहने तथा ट्रेडिंग हानियों संबंधी गंभीर आरोप सामने आने से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर बाजार का विश्वास डगमगा गया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग स्टॉक में गिरावट आई जो यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संकट के कारण उत्पन्न जोखिम विमुखता तथा कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति संबंधी चिंता को दर्शाती है। लिबॉर संबंधी हाल के विवाद ने विश्व का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि कुछ बड़ी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने किस प्रकार कथित रूप से सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बाजार दरों में हेरफेर किया (बॉक्स II.1)।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार में गिरावट

2.12 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार (रिपोर्टकर्ता बैंकों के स्थान के अनुसार) में 2011-12 के दौरान गिरावट देखी गई। यह स्थिति 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान अंतरराष्ट्रीय कारोबार में हुई

बहाली के विपरीत है (सारणी II.2)। देशों के बीच क्रेडिट के प्रवाह में जो कमी आई वह बैंकों द्वारा अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण थी। यह कमी मुख्य रूप से यूरो क्षेत्र के देशों के आपसी दावों में बहुत अधिक थी।

बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

विभिन्न देशों के बीच पूंजी पर्याप्तता के स्तर में भिन्नता

2.13 कई देशों के बैंकों द्वारा अपनी पूंजी की स्थिति सुदृढ़ करने के गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप पूंजी पर्याप्तता के स्तर सुधार आया। तथापि, कुछ यूरोपीय देशों तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी पर्याप्तता के स्तर में गिरावट आई (सारणी II.3)।

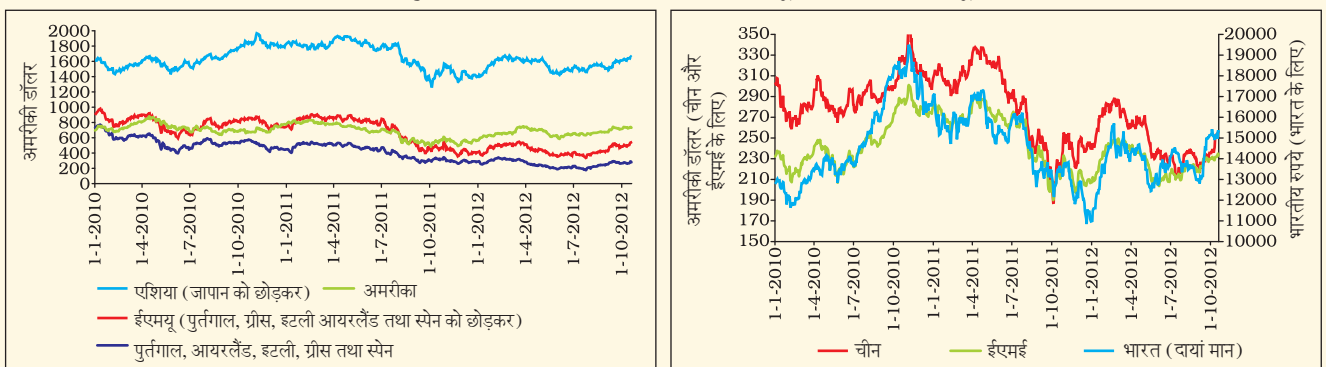
लीवरेज में असमान गिरावट

2.14 विभिन्न देशों के लीवरेज अनुपात से, जिसे कुल आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी (तथा रिजर्व) के रूप में मापा जाता है, बैंकिंग क्षेत्र की डीलीवरेजिंग की असमान प्रवृत्ति स्पष्ट होती है (चार्ट II.5)।

आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार

2.15 वैश्विक स्तर पर 2011 में संकटग्रस्त यूरो क्षेत्र के देशों को छोड़कर बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट II.6)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधिकांश देशों ने संकट के बाद के वर्षों में आस्तियों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया।

चार्ट II.4: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं/ अर्थव्यवस्था समूहों में बैंक स्टॉक सूचकांक



टिप्पणी: ईएमयू का तात्पर्य यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन से है।

स्रोत: थॉमसन रायटर्स, डेटास्ट्रीम।

बॉक्स II.1: लिबॉर दर के निर्धारण संबंधी मुद्दे एवं बैंकों के लिए इसका महत्त्व

हाल की लंदन अंतर-बैंक प्रस्ताव दर (लिबॉर) की हेराफेरी की घटना ने नाजुक वित्तीय बाजार में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। इस घटना ने लिबॉर के परिकलन की पद्धति की कमियों को सामने ला दिया है। यह अत्यधिक प्रयोग की जानेवाली बाजार दर है और कुछ प्रमुख प्लेयर्स ने इसमें हेराफेरी की।

लिबॉर एक बेंचमार्क है जिसका उपयोग लंदन अंतर-बैंक बाजार में गैर-जमानती उधार की लागत का पता लगाने के लिए बैंकों, प्रतिभूतियों में लेनदेन करने वाली संस्थाओं तथा निवेशकों द्वारा किया जाता है। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत के बाद बेंचमार्क के रूप में इसका महत्त्व बढ़ गया है क्योंकि अधिकांश वित्तीय उत्पादों, जैसे- ब्याज दर स्वेप, कारपोरेट ऋण तथा आवासीय बंधकों के लिए यह संदर्भ दर के रूप में कार्य करती है। लिबॉर का प्रकाशन ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है तथा इसकी गणना थॉम्सन रायटर्स द्वारा प्रतिदिन की जाती है। प्रमुख बैंक थॉम्सन रायटर्स को गैर-जमानती निधियाँ उधार लेने की अपनी लागत 15 बार के लिए 10 मुद्राओं में प्रस्तुत करते हैं। प्राप्त हुई दरों में से सबसे अधिक और सबसे कम दरों को छोड़ दिया जाता है तथा शेष दरों का औसत उस दिन की लिबॉर दर की गणना के लिए लिया जाता है।

चूंकि लिबॉर की गणना वास्तविक दरों से न करके 18 सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों के अन्य बैंकों से उधार ले सकने की अनुमानित दर के आधार पर की जाती है, इसलिए बैंक लिबॉर बेंचमार्क को प्रभावित कर सकते हैं। बैंकों ने 2005 से 2008 के दौरान अपनी फर्मों की प्रस्तुतियां कम मात्रा में ऊपर अथवा नीची करके बेंचमार्क को प्रभावित करने का प्रयास किया ताकि उनकी ट्रेडिंग बहियों को लाभ मिल सके। बैंकों ने, विशेष रूप से 2008 से 2009 के दौरान के वित्तीय संकट की चरमावस्था में अपने वित्त की स्थिति बेहतर दिखाने के लिए अपनी प्रस्तुतियों में दरें कम दिखाईं।

इस घटना ने लिबॉर बेंचमार्क के निर्धारण में विनियामक सुधारों की आवश्यकता को सामने ला दिया है। यूके की सरकार ने वित्तीय सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह अपने निदेशक मार्टिन हेटले की अगुवाई में लिबॉर के निर्धारण के फ्रेमवर्क की समीक्षा करे। समिति को संदर्भित विषयों में ये शामिल हैं: (i) लिबॉर के निर्धारण तथा नियंत्रण के लिए वर्तमान फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार; (ii) लिबॉर की हेराफेरी से समुचित रूप से निपटने के लिए प्रतिबंधों की पर्याप्तता तथा परिसीमा; (iii) क्या लिबॉर की विफलता के विश्लेषण से अन्य वैश्विक बेंचमार्कों पर असर पड़ेगा। हेटले समिति ने 10 अगस्त 2012 को सिफारिशों के साथ प्रारंभिक चर्चा-पत्र प्रस्तुत कर दिया है ताकि जनता से

फीडबैक प्राप्त किया जा सके। जनता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर समिति ने 28 सितंबर 2012 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने लिबॉर संबंधी व्यापक सुधार के लिए दस-सूत्री योजना की सिफारिश की जिसे यूके की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रमुख सुधारों में ये शामिल हैं - (i) लिबॉर का प्रशासन तथा लिबॉर को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी वित्तीय सेवा तथा बाजार अधिनियम, 2000 (विनियमित कार्यकलाप) आदेश 2001 के अंतर्गत नियंत्रित कार्यकलापों में आ जाएगी (ii) बीबीए को लिबॉर का दायित्व एक नए प्रशासक को अंतरित कर देना चाहिए (iii) प्रस्तुतकर्ता बैंकों को लेनदेन के आंकड़ों का प्रकट रूप में तथा स्पष्ट उपयोग करना चाहिए ताकि इनका मिलान उनकी प्रस्तुतियों से किया जा सके (iv) यथा समय बीबीए तथा नए प्रशासक द्वारा उन मुद्राओं तथा अवधियों के लिए लिबॉर के संकलन तथा प्रकाशन को बंद कर दिया जाना चाहिए जिनके ट्रेड के आंकड़े अपर्याप्त हों। इसके फलस्वरूप प्रकाशित दरों की संख्या 150 से घटकर 20 रह जाएगी।

इस विवाद ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में और अनिश्चितता पैदा कर दी है तथा प्रमुख बेंचमार्क दरों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली पर बाजार के विश्वास को कम कर दिया है। लिबॉर की हेराफेरी की घटना के बाद कथित रूप से इसमें शामिल कुछ बैंकों के शेयर गिर गये हैं। इस घटना में शामिल बैंकिंग संस्थाओं पर भारी जुर्माना एवं दण्ड लगाए जा सकते हैं क्योंकि इन कंपनियों के विरुद्ध काफी संख्या में मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। इससे तुलन-पत्रों को सुदृढ़ करने का बैंकों का प्रयास बाधित हो सकता है।

इस घटना ने इस बात पर व्यापक बहस की शुरुआत कर दी है कि किस प्रकार अन्य बेंचमार्क दरों एवं सूचकांकों का परिकलन किया जाता है। कुछ बेंचमार्क पहले ही जांच के दायरे में हैं। प्रतिभूति कमीशनों का अंतरराष्ट्रीय संगठन तेल की हाजिर कीमतों की जांच कर रहा है जबकि यूरोपीय कमीशन यूरो अंतर-बैंक प्रस्ताव दर (यूरोबोर) जैसे अन्य वित्तीय बेंचमार्कों की जांच कर रहा है।

संदर्भ:

बीबीए की वेबसाइट <www.bbalibor.com>

यूके सरकार (2012), हेटले रिव्यू ऑफ लिबॉर : इनिशियल डिस्कशन पेपर, लंदन, अगस्त।

यूके सरकार (2012), हेटले रिव्यू ऑफ लिबॉर : फाइनल रिपोर्ट, सितंबर।

वैलेस पी (2012) ट्रेडिंग लिबॉर - हाउ डू यू सॉल्व ए प्राब्लम लाइक लिबॉर? , दि बैंकर।

सारणी II.2: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल आस्तियां	-17.5	0.2	5.8	-1.9
1. बाह्य आस्तियां	-17.5	0.1	5.7	-2.3
ऋण और जमाराशियां	-19.0	-1.0	6.9	-2.3
धारित प्रतिभूतियां और अन्य आस्तियां	-13.2	3.0	2.4	-2.4
2. विदेशी मुद्राओं में स्थानीय आस्तियां	-17.5	0.7	6.9	1.6
कुल देयताएं	-18.0	-0.7	7.4	-0.9
1. बाह्य देयताएं	-18.6	0.2	6.8	-1.4
ऋण तथा जमाराशियां	-21.2	-1.3	5.9	-2.1
प्रतिभूतियों के स्वयं के निर्गम और अन्य देयताएं	-2.0	7.4	11.0	1.7
2. विदेशी मुद्रा में स्थानीय देयताएं	-14.4	-6.1	11.8	2.2

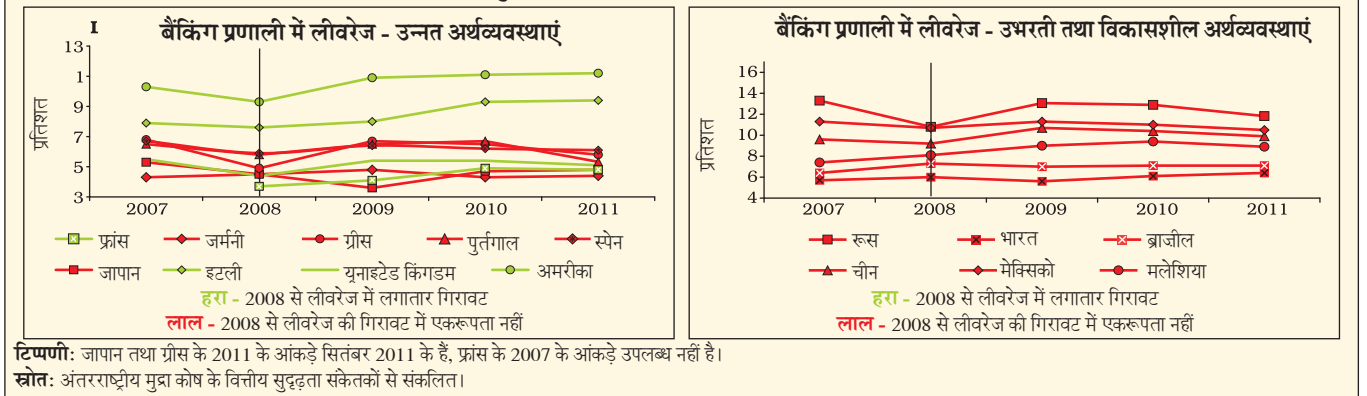
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी से संकलित

3. चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग की प्रवृत्ति

अमरीकी बैंकिंग प्रणाली - तुलन-पत्र को सुधारने तथा पूंजी बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति

2.16 अमरीकी बैंकिंग प्रणाली ने हाल के वित्तीय संकट के बाद अपने तुलन-पत्रों को ठीक करने एवं पूंजी बढ़ाने की दिशा में बहुत प्रगति की। अमरीका के बड़े बैंकों ने अल्पावधि की थोक निधीयन पर अपनी निर्भरता कम की। बैंकों ने चार्ज-ऑफ, राइट-डाउन तथा आस्तियों का निपटान करके एवं टियर-1 पूंजी बढ़ाकर दूषित आस्तियों को कम किया। साथ ही, बैंकों की इक्विटी पूंजी तथा इक्विटी आस्ति अनुपात में सुधार देखा गया (चार्ट II.7)।

चार्ट II.5: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज



सारणी II.3: चुनिंदा देशों के बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

देश	2007	2008	2009	2010	2011	2012
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं						
फ्रांस	-	10.5	12.4	12.7	12.3	-
जर्मनी	12.9	13.6	14.8	16.1	16.4	17.0
ग्रीस	11.2	9.4	11.7	12.2	10.1	-
इटली	10.1	10.4	11.7	12.1	12.7	-
जापान	13.3	12.3	12.4	13.3	14.2	-
पुर्तगाल	10.5	9.4	10.5	10.3	9.8	12.3
स्पेन	11.4	11.3	12.2	11.9	12.4	-
यूनाइटेड किंगडम	12.6	12.9	14.8	15.9	15.7	-
अमरीका	12.8	12.8	14.3	15.3	15.3	15.3
उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
रूस	15.5	16.8	20.9	18.1	14.7	14.6
चीन	8.4	12.0	11.4	12.2	12.7	12.9
भारत	12.3	13.0	13.2	13.6	14.2	13.6
मलेशिया	14.8	16.1	18.2	17.5	17.7	17.2
ब्राजील	18.8	18.3	19.0	17.7	17.3	17.2
मेक्सिको	15.9	15.3	16.5	16.9	15.7	15.7

टिप्पणी: - उपलब्ध नहीं
 जापान तथा ग्रीस के 2011 के आंकड़े सितंबर के हैं।
 जर्मनी, पुर्तगाल, अमरीका, चीन, भारत, मलेशिया तथा ब्राजील के 2012 के आंकड़े जून के हैं और मेक्सिको और रूस के आंकड़े मार्च के हैं।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

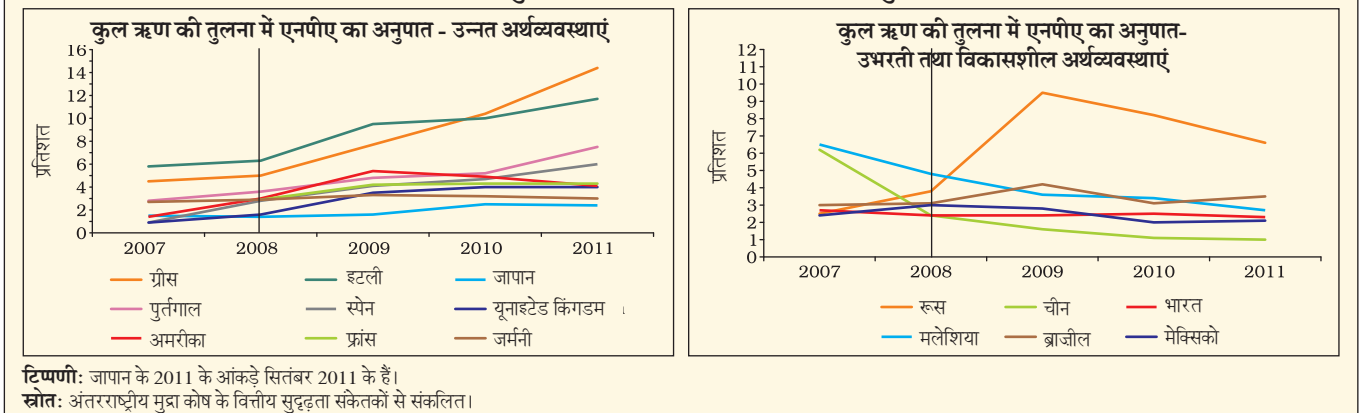
अमरीकी बैंकों के दबाव परीक्षण में बेहतर सुदृढ़ता के लक्षण

2.17 व्यापक पूंजी विश्लेषण तथा समीक्षा के अंतर्गत मार्च 2012 में किया गया दबाव परीक्षण दर्शाता है कि अधिकांश 19 बैंकिंग फर्मों के पास आर्थिक तथा वित्तीय दबाव झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी है और उसके बाद भी ऋण देने की उनकी क्षमता बनी रहेगी।

अमरीकी बैंकों के क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार

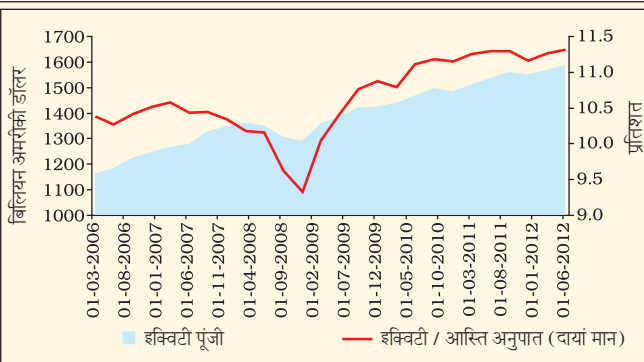
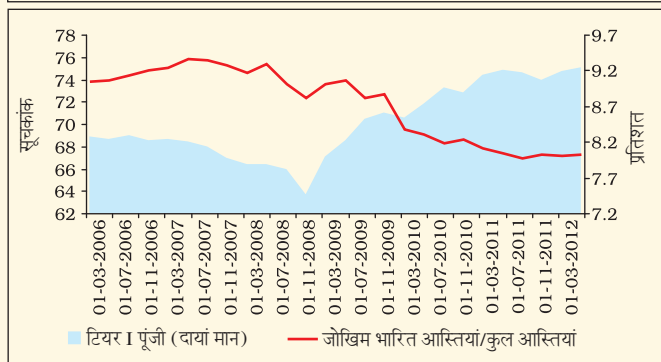
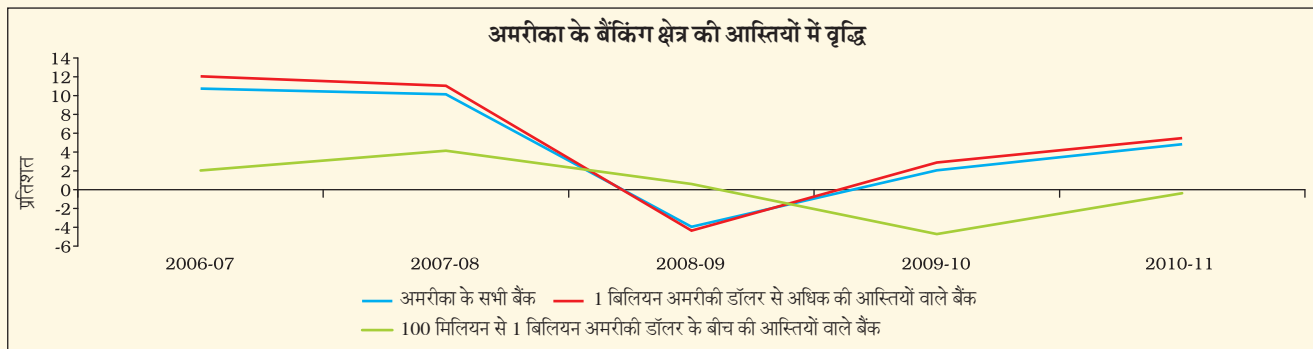
2.18 औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, परंतु स्थावर संपदा तथा व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि कम रही। ऋण पोर्टफोलियो की समग्र चूक दरों में गिरावट आई परंतु आस्ति गुणवत्ता की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में जो अंतर है वह चिंता का विषय बना हुआ है (चार्ट II.8)।

चार्ट II.6: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में आस्तियों की गुणवत्ता



चार्ट II.7: अमरीकी बैंकिंग प्रणाली की प्रगति

अमरीका के बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों में वृद्धि



स्रोत: ब्लूमबर्ग तथा फेडरल डिपॉजिट कार्पोरेशन के डेटाबेस

यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली - जोखिम उच्च स्तर पर बना हुआ है

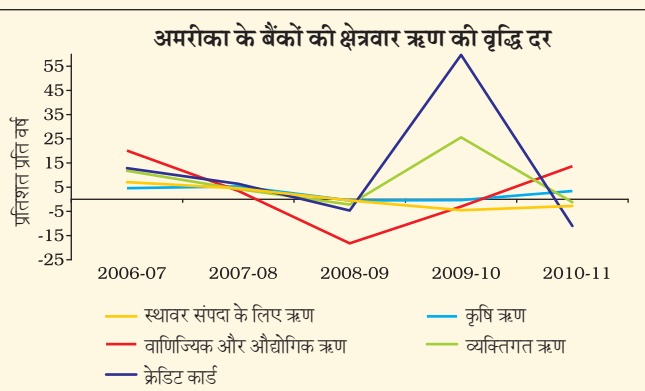
2.19 यूरो क्षेत्र के वर्तमान ऋण संकट ने बैंकों तथा सरकारी ऋणों के बीच के दुश्चक्र को रेखांकित किया है (बॉक्स II. 2)। उनकी बढ़ती अंतर-संबद्धता ने यूरोपीय यूनियन के बैंकिंग क्षेत्र के बाजार को लंबे समय तक तहस-नहस कर दिया जिसके चलते निधियों की लागत एवं उपलब्धता पर प्रतिकूल असर पड़ा।

यूरो क्षेत्र संकट के दौरान की जोखिम विमुखाता ने अंतर-बैंक बाजार को अचल बना दिया

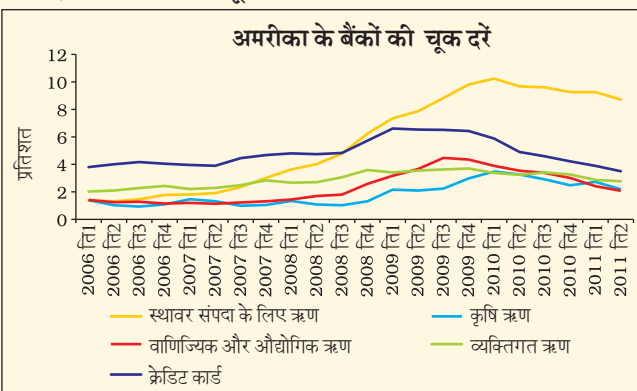
2.20 यूरो क्षेत्र के बैंक ग्राहकों की जमाराशियों के बजाय थोक निधियों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इन बैंकों का कुल देयताओं की तुलना में आवासीय जमाराशियों का अनुपात लगभग 51 प्रतिशत था (चार्ट II.9)। हाल के यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संकट के दौरान निधियन की ऐसी व्यवस्था ने यूरोपीय यूनियन के बैंकों को अधिक

चार्ट II.8: अमरीकी बैंकों का क्षेत्रवार ऋण तथा चूक

अमरीका के बैंकों की क्षेत्रवार ऋण की वृद्धि दर



अमरीका के बैंकों की चूक दरें



स्रोत: एफडीआईसी डेटाबेस, फ्रेड इकोनॉमिक डेटा, सेंट लुइस फेड के आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

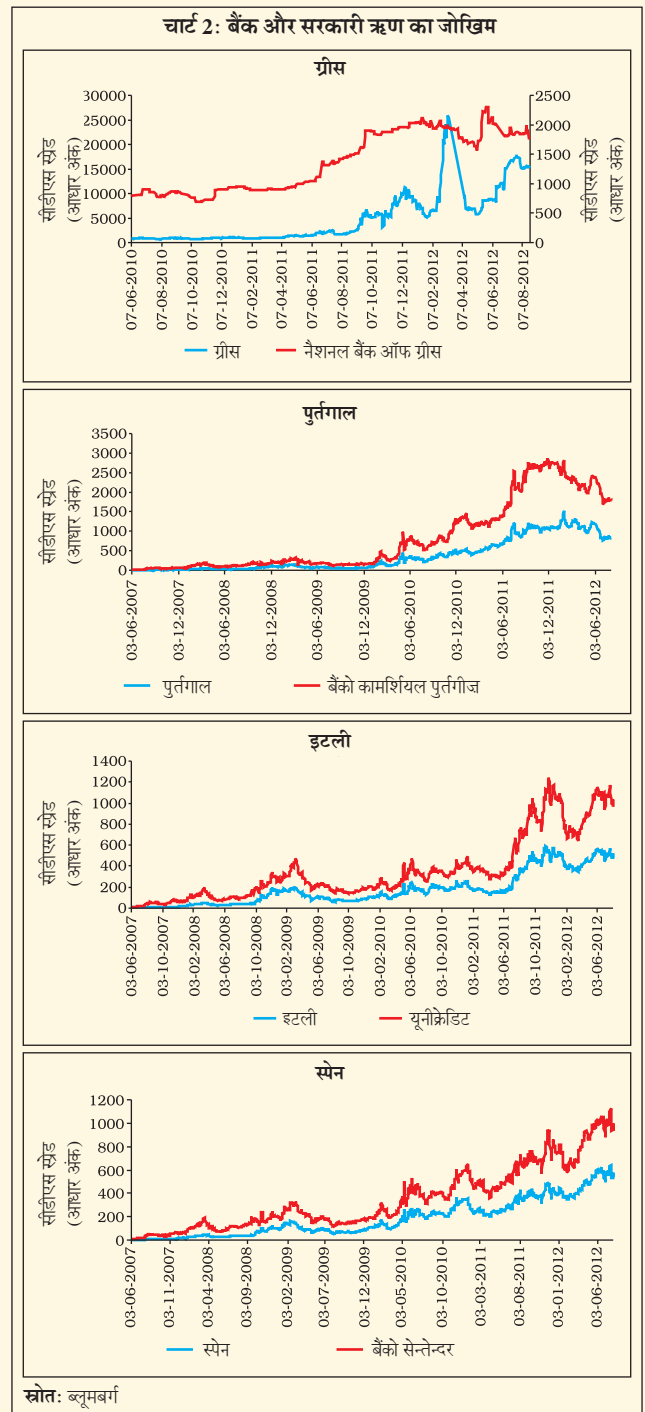
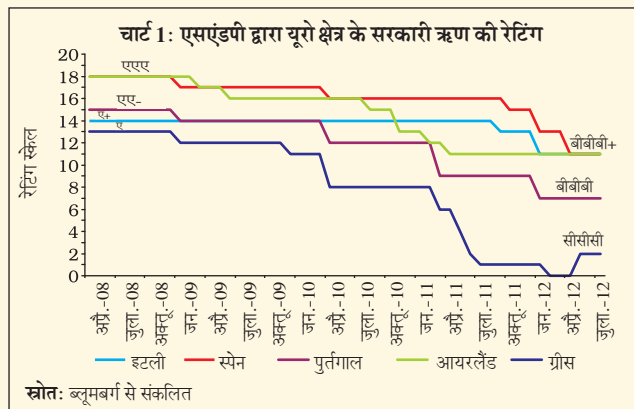
बॉक्स II.2 यूरो क्षेत्र का संकट तथा सरकारी ऋण तथा बैंक का आपसी संबंध : सरकारी ऋण की रेटिंग को कम किया जाना तथा वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए इसका महत्व

हाल का वैश्विक वित्तीय संकट और यूरो क्षेत्र के ऋण संकट का गहराना बैंक और सरकारी ऋण संबंधी जोखिम की अंतर-संबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। विविध अनुसंधानमूलक अध्ययनों से राजकोषीय और वित्तीय संकट के बीच के संबंध का पता चलता है। राजकोषीय और वित्तीय उथल-पुथल के दौरान अंतरण के माध्यमों की चर्चा करते हुए रैनहार्ट और रोगोफ (2011) ने चार प्रकार के विशिष्ट तथ्यों का एक सेट प्रस्तुत किया। पहला, बैंकिंग संकट के पहले निजी और सरकारी ऋणों में तीव्र वृद्धि होती है। दूसरा, आम तौर पर बैंकिंग संकट, चाहे वह देश में पैदा हुआ हो या विदेश से आया हो, के साथ-साथ या बाद में सरकारी ऋण संकट होता है। तीसरा, सरकारी ऋण संकट से पहले सार्वजनिक उधार में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसा भी होता है कि सरकार का अतिरिक्त 'छुपा हुआ ऋण' (घरेलू सरकारी ऋण तथा आकस्मिक निजी ऋण) भी होता है। चौथा, सरकारी ऋण तथा बैंकिंग संकट - दोनों से पहले ऋण की संरचना अल्पावधि की ओर झुक जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि वित्तीय संकट से मुद्रा संबंधी संकट की शुरुआत होती है तो विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की चुकौती की सरकार की क्षमता बाधित होती है जिससे चूक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान संबंधित देशों द्वारा बैंकों का बचाव किए जाने से ऋण संबंधी जोखिम वित्तीय क्षेत्र से राष्ट्रीय सरकार में अंतरित हो गया तथा इससे सरकारी ऋण संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी हुई (आचार्य तथा अन्य 2010)। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से संकट का अंतरण सामान्यतः सरकार से बैंकों की ओर होता है जिसमें सरकारी ऋण की चुकौती में हुई चूक से बैंक-संकट की शुरुआत होती है (केप्रियो एंड होनहैन 2008)। जीडीपी की तुलना में ऋण के उच्चतर अनुपात सहित कमजोर आर्थिक वृद्धि के चलते यूरो क्षेत्र के देशों-ग्रीस, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल तथा स्पेन (जीआईआईपीएस) - की सरकारी ऋण की रेटिंग को बारंबार कम किया गया (चार्ट 1)। सरकारी ऋण के जोखिम के बढ़ने से बैंक भी प्रभावित हो गये क्योंकि सरकारी बांडों के वे प्रमुख धारक थे।

ऐसे कई माध्यम हैं जिनसे सरकारी ऋण संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी होने से बैंकों की निधायन की लागत में बढ़ोतरी होती है: (i) सरकारी ऋण की धारिता पर होने वाली हानि से बैंकों के तुलन-पत्र प्रभावित होते हैं, उनकी जोखिम प्रवणता में बढ़ोतरी होती है तथा निधि का मिलना कठिन हो जाता है एवं उसकी लागत अधिक हो जाती है; (ii) सरकारी ऋण का जोखिम उच्चतर रहने से संपाश्विक के मूल्य में कमी आती है जबकि बैंक इन संपाश्विकों का उपयोग थोक निधायन के लिए एवं केंद्रीय बैंक से चलनिधि प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं; (iii) सरकारी ऋण को डाउनग्रेड किए जाने से घरेलू बैंकों की रेटिंग भी कम हो जाती है, जिससे उनके थोक निधायन की लागत में बढ़ोतरी होती है एवं बाजार में जाने की उनकी क्षमता बाधित होती है; तथा (iv) सरकारी ऋण के स्तर में कमी आने पर बैंकों के निधायन संबंधी उन लाभों में कमी आती है जिनसे वे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सरकारी गारंटी प्राप्त करते हैं (सीजीएफएस-बीआईएस 2011)।

सरकार की माली हालत एवं उनके बैंक के बीच का आपसी संबंध यूरो क्षेत्र के जीआईआईपीएस देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि सीडीएस स्प्रेड के रूप में मापा जाने वाला सरकारी तथा बैंक जोखिम (संबंधित देश का सबसे बड़ा बैंक) संकट के दौरान एक ही दिशा में चलता है (चार्ट 2)।



(जारी...)

(समाप्त....)

ग्रीस की राजनीतिक स्थिति एवं स्पेन की बैंकिंग प्रणाली द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों से जुड़े घटनाक्रमों से सरकारी ऋण तथा बैंकिंग संबंधी दबाव में वृद्धि हुई क्योंकि यूरो क्षेत्र में संकट के प्रबंधन के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकारों के बीच समन्वय की कमी से निवेशक चिंतित थे।

संदर्भ:

आचार्य, विराल वी., डिचेसलर, आई एंड स्वनबल (2011), “ए पायरिक विकटरी? बैंक बेल आउट एंड सोवरेन क्रेडिट रिस्क”, एनबीईआर वर्किंग पेपर्स 17136, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च।

बार्थ, जेम्स आर., अपनार्ड प्रभा एंड ग्रेग यून (2012), “दि यूरोजोन फिनांसियल

क्राइसिस: रोल ऑफ इंटरडिपेंडेन्सीज बिटवीन बैंक एंड सोवरेन रिस्क”, जर्नल ऑफ फिनांसियल इकॉनॉमिक पालिसी, खंड 4

कैप्रिओ, गेरार्ड एंड पैट्रिक होनाहन (2008): “बैंकिंग क्राइसिस”, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकॉनॉमिक्स, विल्यमस कॉलेज।

सीजीएफएस-बीआईएस (2011), “दि इपैक्ट ऑफ सोवरेन क्रेडिट रिस्क ऑन बैंक फंडिंग कंडीशन्स” सीजीएफएस पेपर्स नं. 43, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स।

रोगोफ, केनिथ एस. एंड कार्मेन एम. रैनहार्ट (2011), “ए डिफेड ऑफ डेट” एनबीईआर वर्किंग पेपर्स 16827, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च।

नाजुक बना दिया क्योंकि इसके चलते उनकी निधीयन की लागत अवहनीय स्तर तक बढ़ गई। इसमें यूरोपीय बैंकों के लिए थोक निधीयन बाजार अचल हो गया। ग्रीस, इटली तथा स्पेन जैसे देशों में अनिवासियों की जमाराशि सहित ग्राहकों की जमाराशियों में गिरावट आई। यूरिबोर-ओआईएस स्प्रेड में, जो गैर-जमानती अंतर बैंक बाजारों में प्रतिपक्षी जोखिम का एक संकेतक है, 2011 की दूसरी छमाही में तेजी से वृद्धि हुई, परंतु बाद की अवधि में इसमें गिरावट आई (चार्ट II.9)।

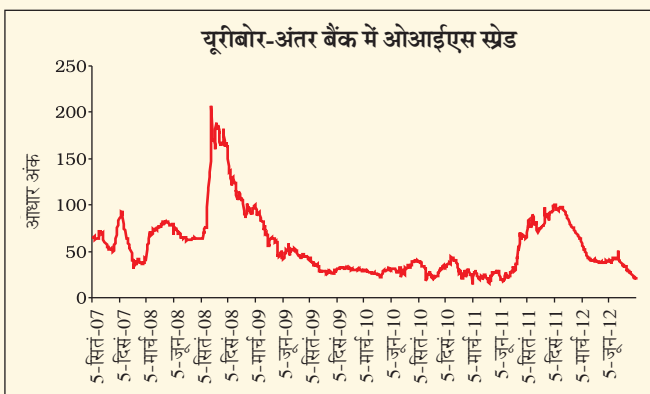
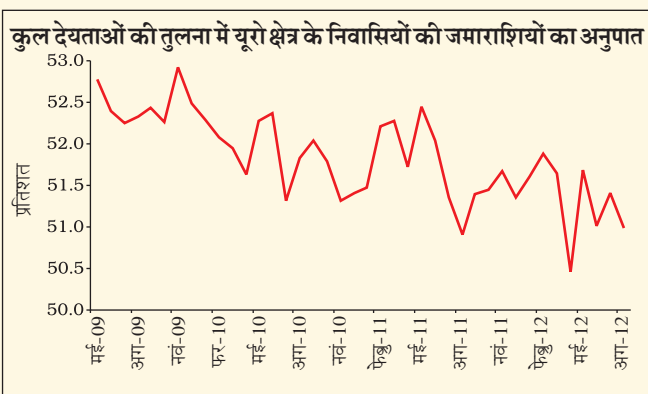
2.21 यूरोपीय बैंकों के निधीयन संबंधी दबाव को कम करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 21 दिसंबर 2011 तथा 29 फरवरी 2012 को दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) किया जिसकी राशि 1 ट्रिलियन यूरो से भी अधिक थी। इसने यूरोपीय बैंकों के निधीयन संबंधी दबावों का अस्थायी तौर पर समाधान किया और वित्तीय दबाव को कम किया। परंतु यूरोपीय बैंकों ने एलटीआरओ

निधियों का उपयोग निजी क्षेत्र को कर्ज देने में न करके तुलन-पत्रों को बचाने में किया (चार्ट II.10)। एलटीआरओ निधि का अधिकांश हिस्सा यूरोपीय केंद्रीय बैंक में ही जमा कर दिया गया।

पूंजी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, परंतु चिंताएं बनी हुई हैं

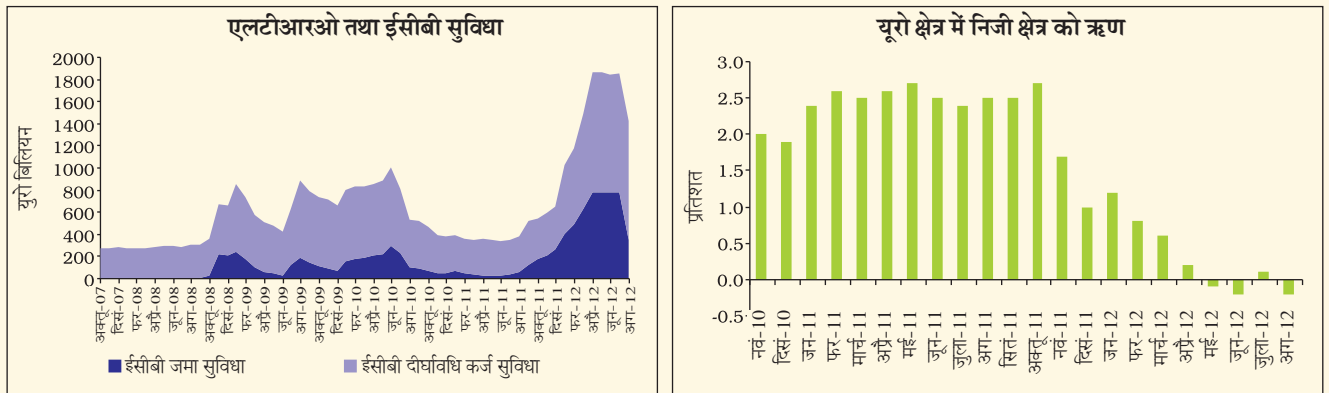
2.22 संकट के गहराने के साथ आस्ति की गुणवत्ता, पूंजी बफर के आकार तथा भविष्य की ऋण हानियों से निपटने की बैंकों की क्षमता के प्रति बाजार अधिक चिंतित हुआ। इन चिंताओं को दूर करने के लिए यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने बैंकों की पूंजी की जरूरत का आकलन करने के लिए नवंबर 2011 में 71 बैंकों का यूरोपीय यूनियन-व्यापी दबाव परीक्षण तथा पूंजी संबंधी परीक्षण किया एवं बैंकों को सूचित किया कि वे अस्थायी पूंजी बफर का निर्माण करें ताकि 30 जून 2012 तक 9 प्रतिशत का कोर टियर-1 अनुपात प्राप्त किया जा सके। यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने पाया कि यूरोप के 27 बैंकों को 9 प्रतिशत का टियर-1 अनुपात पूरा करने के लिए 76 बिलियन यूरो

चार्ट II.9: यूरोपीय बैंकों के निधीयन का ढांचा तथा अंतर-बैंक बाजार



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट II.10: यूरो क्षेत्र में एलटीआरओ तथा निजी क्षेत्र को ऋण



स्रोत: ब्लूमबर्ग तथा यूरोपियन सेंट्रल बैंक

की कुल पूंजी जुटानी होगी। यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी द्वारा 03 अक्टूबर 2012 को जारी अंतिम रिपोर्ट दर्शाती है कि 27 बैंकों ने जून 2012 तक 116 बिलियन यूरो जोड़कर अपनी पूंजी की स्थिति सुदृढ़ की। इसका परिणाम सकारात्मक होने पर भी चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि सर्वेक्षण में शामिल कुछ बैंकों, विशेष रूप से ग्रीस और स्पेन के बैंकों को बेलआउट की जरूरत थी।

यूरोपीय बैंक जीआईआईपीएस देशों के प्रति एक्सपोजर की डिलीवरेजिंग कर रहे हैं

2.23 यूरोपीय बैंक यूरो क्षेत्र के प्रभावित देशों, विशेष रूप से ग्रीस के प्रति अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। बीआईएस के आंकड़े दर्शाते हैं कि राइट-डाउन तथा आस्तियों की बिक्री के बाद ग्रीस के सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण के संबंध में उनका कुल एक्सपोजर तिमाही-दर-तिमाही आधार पर मार्च 2012 के अंत में 70 प्रतिशत से भी अधिक कम हो गया (चार्ट II.11)।

यूके की बैंकिंग प्रणाली- यूरो क्षेत्र संकट का संक्रमण

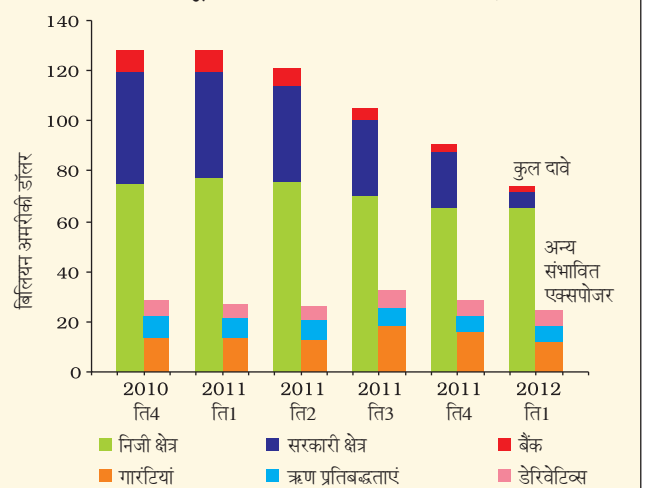
2.24 यूरो क्षेत्र के संकट ने यूके की वित्तीय प्रणाली को प्रभावित किया तथा इसके चलते यूके की अर्थव्यवस्था की संभावना में उल्लेखनीय गिरावट आई। यद्यपि यूके के बैंकों ने हानि से बचाव के लिए पूंजी के रूप में काफी बफर बना लिया था, फिर भी वे बाजार की अनिश्चितता में हुई सामान्य बढ़ोतरी तथा यूरो क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ी व्यापक जोखिम विमुखता से प्रभावित हुए। इसके परिणामस्वरूप बैंकों की निधीयन लागत में तेजी से वृद्धि हुई जिससे यूके की पारिवारिक इकाइयों तथा कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें बढ़ गई तथा ऋण की उपलब्धता में कमी आई।

प्राधिकारियों द्वारा नीतिगत कार्रवाइयों के बावजूद बैंकिंग प्रणाली से मिलने वाले कर्ज का प्रवाह बाधित हुआ जबकि पारिवारिक इकाइयों तथा कई कारोबार इस पर नितांत निर्भर रहते हैं। हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि यूके के कारोबारियों को दिए गए कर्ज में कमी आई है (चार्ट II.12)।

चीन की बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि जारी

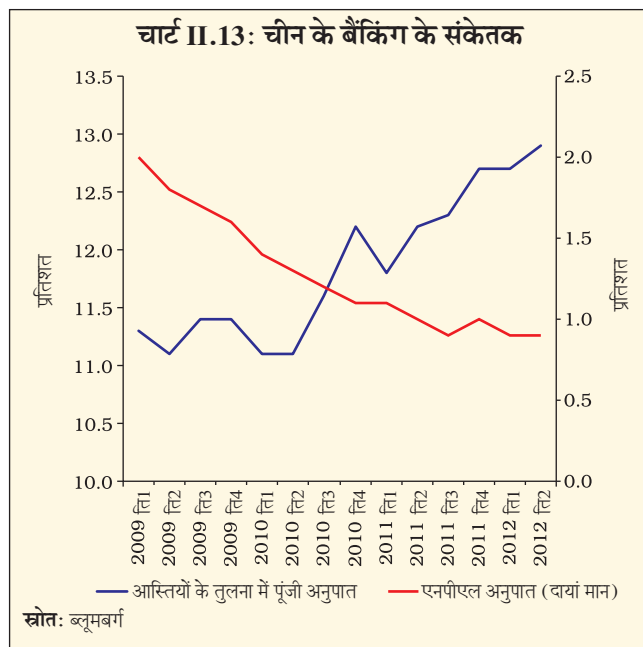
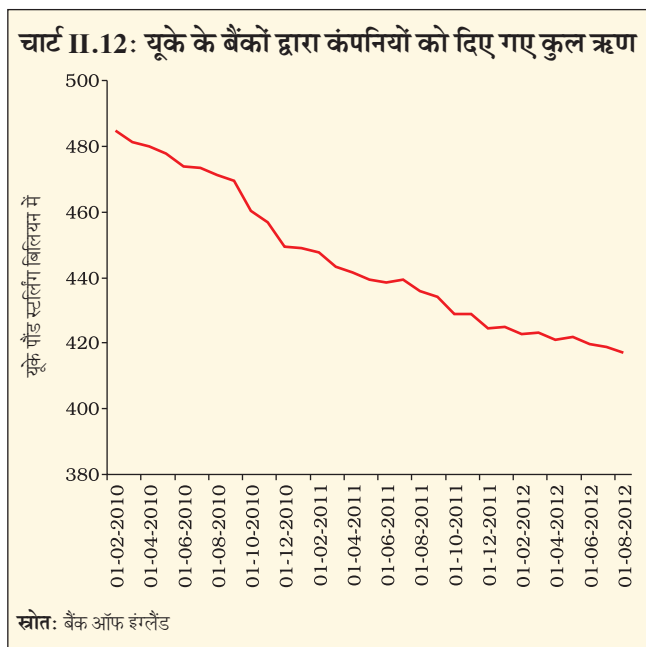
2.25 25 चीन की बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि 2011 में आस्तियों की तुलना में पूंजी के उच्चतर अनुपात एवं केवल लगभग 1 प्रतिशत के अनर्जक ऋण (एनपीएल) के साथ जारी रही (चार्ट II.13)। तथापि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आने तथा उसके प्रॉपर्टी बाजारों में

चार्ट II.11: यूरोपीय बैंकों का ग्रीस के प्रति एक्सपोजर



टिप्पणी: कुल दावों में यूरोपीय बैंकों का निजी, सरकारी तथा बैंकिंग क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर शामिल है तथा अन्य संभावित एक्सपोजर में गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं तथा डेरिवेटिव्स शामिल हैं।

स्रोत: ब्लूमबर्ग



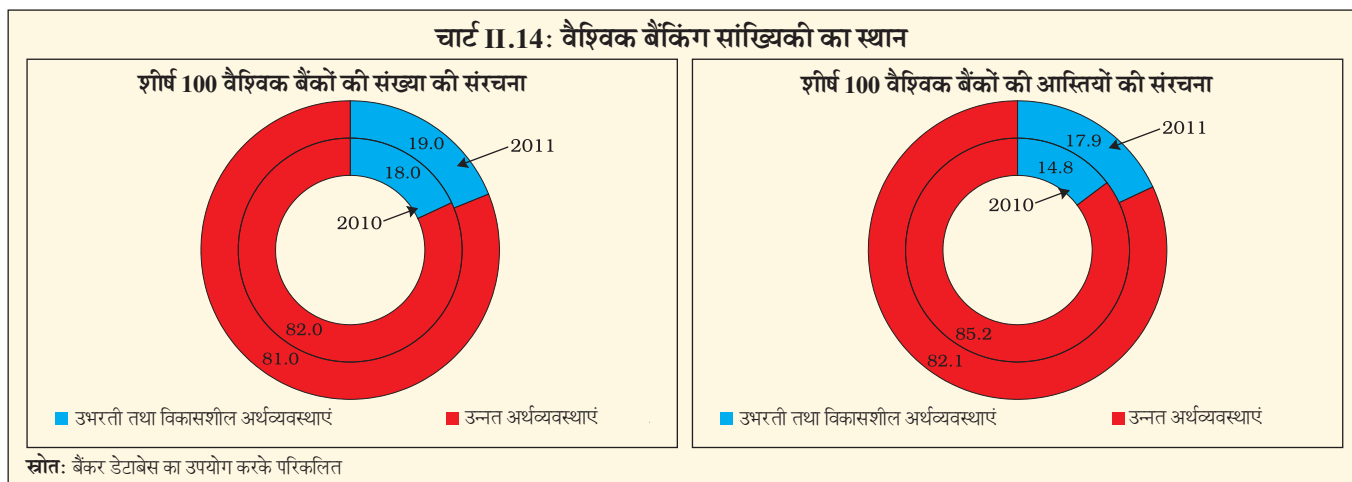
भारी एक्सपोजर के चलते उसके बैंकिंग उद्योग की वृद्धि को बनाए रखना कठिन कार्य होगा।

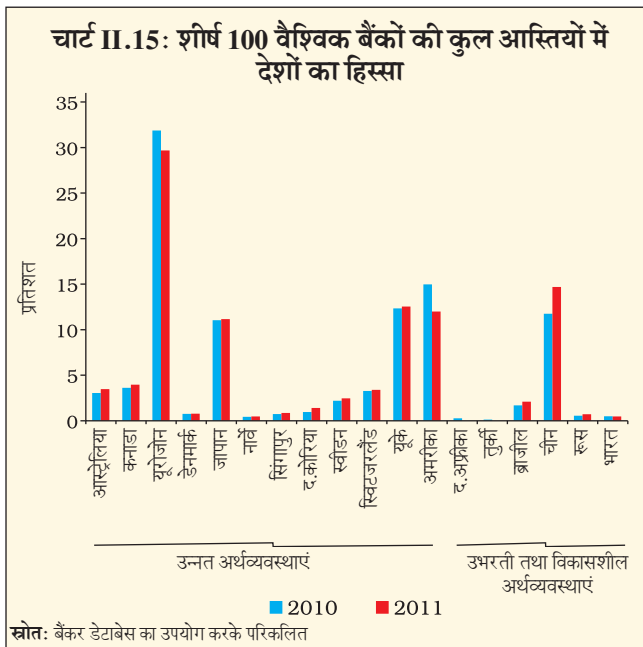
4. शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण

वैश्विक बैंकिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हिस्से में वृद्धि जारी

2.26 बैंकर डेटाबेस द्वारा किए गए शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का विश्लेषण दर्शाता है कि 2011 में वैश्विक बैंकिंग कारोबार में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर थोड़ी उन्मुख होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जैसा कि शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों

की संख्या एवं आस्तियों की संरचना - दोनों से स्पष्ट होता है (चार्ट II.14)। यह बदलाव उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज में निरंतर वृद्धि एवं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज की वृद्धि दर में आई गिरावट को दर्शाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2010 से 2011 के बीच आस्तियों के हिस्से में जो गिरावट आई वह मुख्यतः अमरीकी और यूरोपीय बैंकों में केंद्रित थी (चार्ट II.15)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच चीन के बैंकों ने शीर्ष 100 बैंकों की रेटिंग में उल्लेखनीय सुधार दिखाया जिससे चीन के 4 बैंकों को टियर 1 पूंजी आधार पर शीर्ष 10 बैंकों में पहली बार स्थान प्राप्त हुआ।



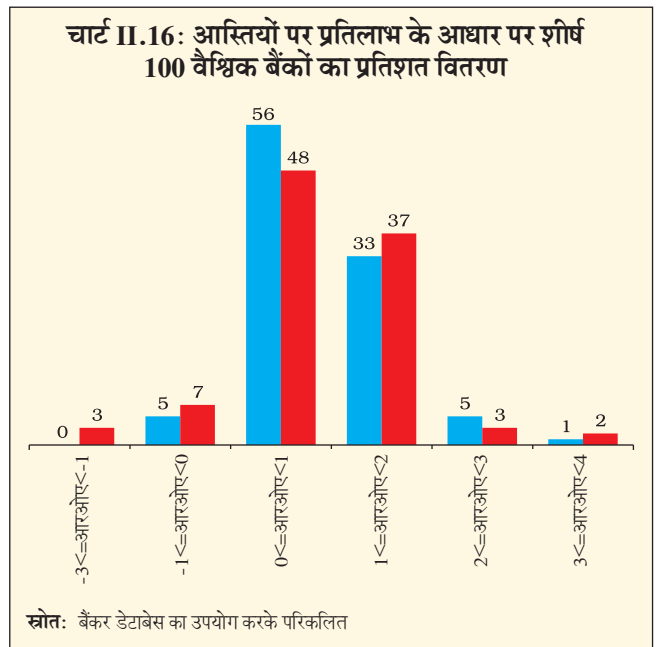


वैश्विक बैंकों की लाभप्रदता का स्तर कम रहा

2.27 शीर्ष 100 बैंकों के लाभ में 2011 के दौरान गिरावट आई जबकि इन बैंकों ने वित्तीय संकट के बाद लाभ की स्थिति में सुधार किया था। इन बैंकों का सकल लाभ 2010 के 709 बिलियन अमरीकी डॉलर से मामूली घटकर 2011 में 702 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। इसके अलावा, 2011 में हानि उठाने वाले बैंकों (आस्तियों पर ऋणात्मक प्रतिलाभ (आरओए) दर्ज करने वाले) का प्रतिशत भी 2010 के 5 से बढ़कर 10 हो गया (चार्ट II.16)।

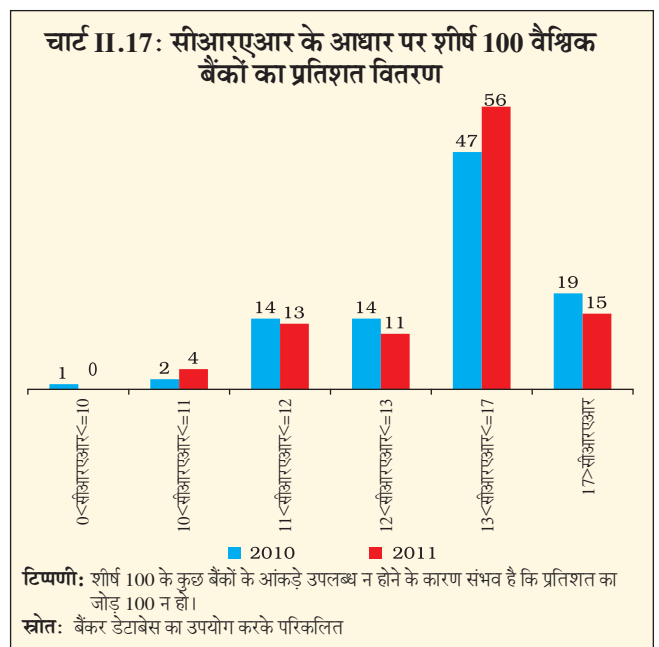
वैश्विक बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता की अपनी स्थिति मजबूत की

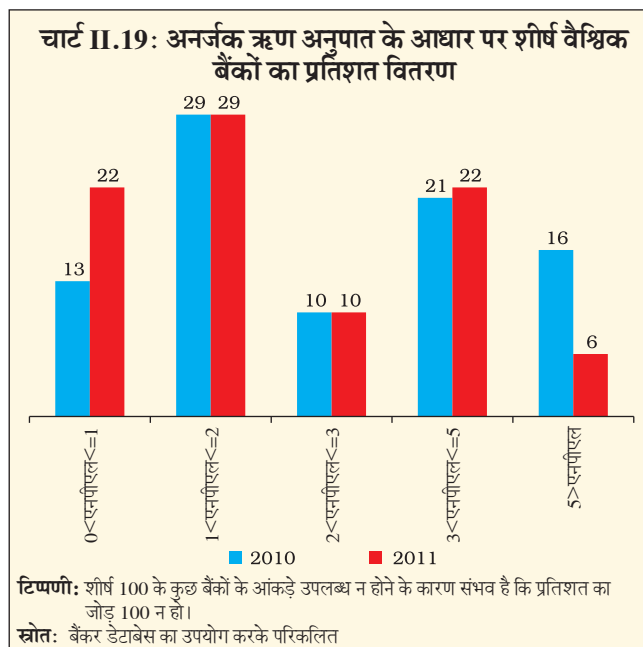
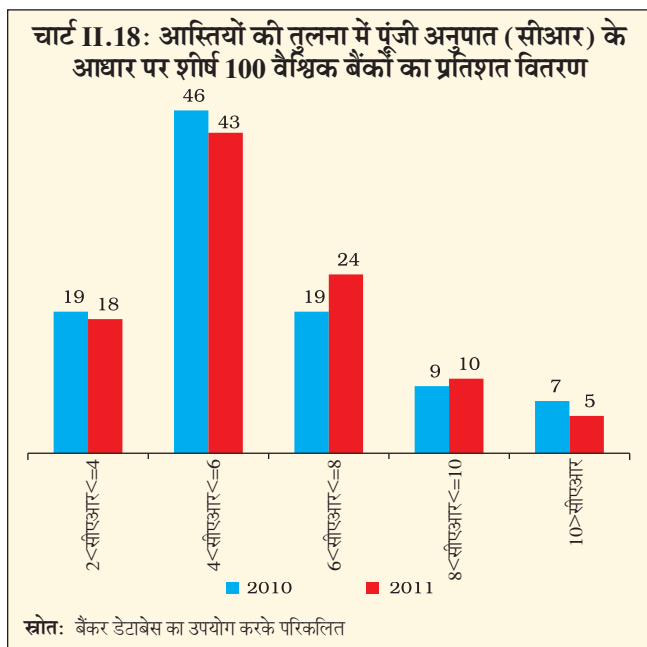
2.28 शीर्ष 100 बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्थिति से स्पष्ट होता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात की दृष्टि से उच्चतर श्रेणी अर्थात् 13 से 17 प्रतिशत वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई जो बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने के वैश्विक प्रयास को दर्शाता है। परंतु 17 प्रतिशत से अधिक के सीआरएआर के दायरे में आनेवाले बैंकों की संख्या में गिरावट आई (चार्ट II.17)। शीर्ष सभी 100 बैंकों (एक को छोड़कर जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) की स्थिति दर्शाती है कि उनकी पूंजी पर्याप्तता का स्तर बीसीबीएस द्वारा बासेल II के अंतर्गत निर्धारित 8 प्रतिशत के सीआरएआर से अधिक है।



वैश्विक बैंकों की डिलीवरेजिंग में कुछ प्रगति हुई

2.29 वैश्विक बैंकों को डिलीवरेज करने के लिए दबाव के बीच, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, बैंकों ने अपने लीवरेज को कम करने में कुछ प्रगति की है (चार्ट II.18)। 2011 के अंत में 4 प्रतिशत से कम तथा 4-6 प्रतिशत के बीच आस्तियों





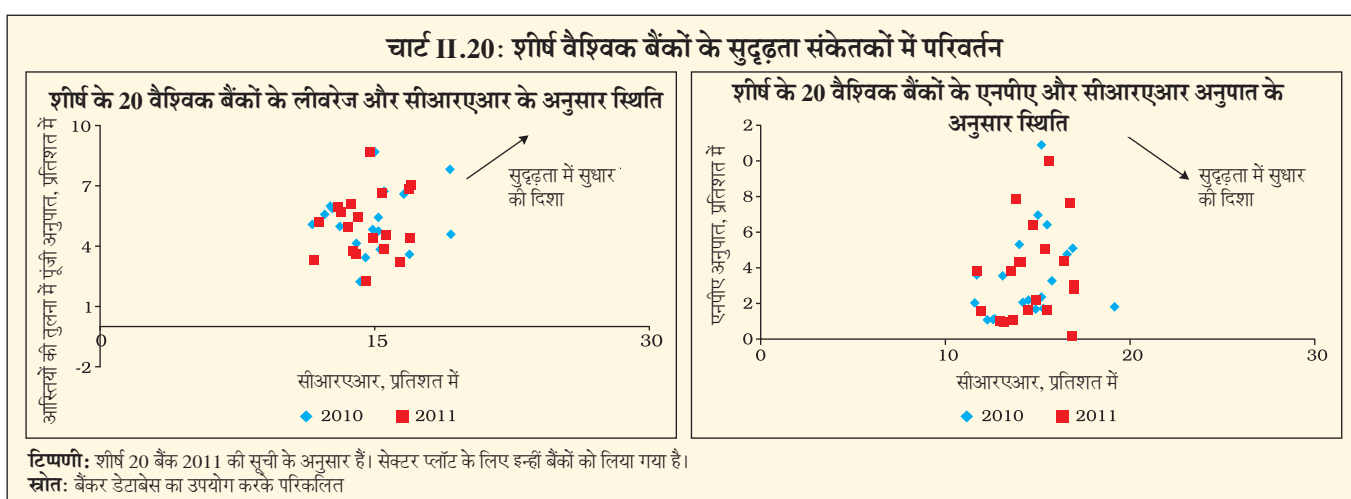
की तुलना में पूंजी अनुपात, जोकि वित्तीय लीवरेज का एक माप है, के साथ अत्यधिक लीवरेज वाले बैंकों की संख्या में कमी आई जबकि 6-8 प्रतिशत के दायरे वाले बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

वैश्विक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

2.30 अनिश्चित वैश्विक वित्तीय माहौल के बीच वैश्विक बैंकों ने अपनी आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार दर्शाया। 5 प्रतिशत से कम के अनर्जक ऋण अनुपात वाले बैंकों की संख्या

16 से घटकर 6 रह गई है (चार्ट II.19)। इसके अतिरिक्त कम अनर्जक आस्ति अनुपात अर्थात् 0-1 प्रतिशत वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई।

2.31 तीन संकेतकों अर्थात् सीआरएआर, लीवरेज और एनपीए अनुपात शामिल करके तैयार किए गए स्कैटर प्लॉट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 तथा 2011 के बीच बैंक जहां अपने सीआरएआर बढ़ाने में लगे थे वहीं बैंकों के लीवरेज तथा एनपीए अनुपातों में मामूली सुधार दिखाई दिया (चार्ट II.20)।



5. वैश्विक नीतिगत सुधार

बासेल नियमों के कार्यान्वयन में प्रगति

2.32 बैंकिंग पर्यवेक्षण के बासेल नियम अर्थात् बासेल II, बासेल II.5 तथा बासेल III का लक्ष्य वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करना है। इन नियमों का विभिन्न देशों में समय पर तथा समान रूप से कार्यान्वयन जरूरी है ताकि वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति अपने सदस्य देशों के बीच बासेल नियमों के कार्यान्वयन का एक मूल्यांकन कर रहा है। बीसीबीएस की अक्टूबर 2012 की बासेल III के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट दर्शाती है कि अनेक सदस्य देशों द्वारा अभी भी दिशा-निर्देश जारी किए जाने बाकी हैं तथा जिन देशों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनमें इस बात की संभावना है कि उनके देश का मानदंड वैश्विक स्तर पर सहमत मानदंडों से कमजोर हो। जी-20 के कुछ देशों, जैसे भारत, जापान, चीन तथा सउदी अरब ने 2013 की शुरुआत से बासेल III के कार्यान्वयन के लिए अंतिम नियमों की घोषणा पहले ही कर दी है, परंतु अधिकांश देश प्रारूपण तथा विचार-विमर्श के स्तर पर हैं। बासेल III के संबंधी विधान का प्रारूप प्रकाशित हो जाने के बाद अमरीका तथा यूरोपीय यूनियन अंतिम नियम के करीब पहुंच गये हैं।

प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सुधार

2.33 बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति ने नवंबर 2011 में वैश्विक प्रणालीगत महत्त्व के आकलन एवं बड़ी संस्थाओं, अर्थात् वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों, की अतिरिक्त हानि सहने की क्षमता को मात्रात्मक रूप देने के लिए अंतिम नियम जारी किए। इसका तर्काधार इन संस्थाओं द्वारा वैश्विक वित्तीय क्षेत्र को हो सकने वाले जोखिमों को रोकना था तथा इसमें वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान करना एवं प्रणालीगत महत्त्व में बढ़ोतरी होने पर सामान्य इक्विटी द्वारा अतिरिक्त हानि सहने की पूंजी अपेक्षा को पूरा करना था। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बैंकों की प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जा चुकी है जिसे वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाएगा एवं इसकी प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत दृष्टि

से महत्वपूर्ण बैंकों के संशोधित मानकों का कार्यान्वयन 2016 से चरणबद्ध रूप में किया जाएगा।

प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के लिए ढांचा

2.34 जी-20 देशों के नेताओं ने बीसीबीएस एवं वित्तीय स्थिरता बोर्ड से अनुरोध किया कि वे प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के लिए जोखिम कम करने का एक समुचित ढांचा विकसित करें। तदनुसार, बीसीबीएस ने जून 2012 में एक परामर्शी दस्तावेज तैयार किया जिसमें प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के संबंध में ढांचा दिया गया था। डी-एसआईबी का ढांचा जी-एसआईबी ढांचे का अनुपूरक होगा और घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की विफलता का आसार घरेलू अर्थव्यवस्था तक सीमित रहेगा। जी-एसआईबी ढांचे के विपरीत डी-एसआईबी ढांचा नीति संबंधी उपायों के मूल्यांकन एवं उपयोग हेतु घरेलू वित्तीय प्रणाली की ढांचागत विशेषताओं के अनुरूप ढालने में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की काफी छूट देता है। इन सिद्धांतों में यह अपेक्षा है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी घरेलू वित्तीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत जोखिम का आकलन करें, और जोखिमों का आकलन बैंक विशिष्ट कारकों-जैसे आकार, अंतर-संबद्धता, वैकल्पिक/वित्तीय संस्थागत ढांचा तथा जटिलता-को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। बीसीबीएस ने विचार विमर्श की प्रक्रिया के आधार पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के विनियमन के लिए अक्टूबर 2012 में अंतिम ढांचे का प्रकाशन किया।

शैडो बैंकिंग प्रणाली की निगरानी और विनियमन

2.35 वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने अप्रैल 2012 में शैडो बैंकिंग प्रणाली को “संस्थाओं के बीच कर्ज संबंधी मध्यस्थन तथा कार्यकलाप जो नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर किये गये हों” के रूप में परिभाषित किया है।

2.36 कैन्स में नवंबर 2011 में हुए शिखर सम्मेलन में जी-20 के नेतागण शैडो बैंकिंग की निगरानी और विनियमन को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए और उन्होंने एफएसबी की प्राथमिक सिफारिशों पर उसकी कार्य-योजना के साथ सहमति दी ताकि 2012 के दौरान उसे और विकसित किया जा सके। एफएसबी ने द्विस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है। पहला, एफएसबी अपनी वार्षिक निगरानी संबंधी कार्य जारी रखते हुए निगरानी के ढांचे को विकसित करेगा ताकि वैश्विक

प्रवृत्ति तथा जोखिमों का आकलन किया जा सके और इस प्रक्रिया में और अधिक देश भाग लेंगे। दूसरा, एफएसबी शैडो बैंकिंग प्रणाली के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकतानुसार सिफारिशें देगा ताकि संभावित प्रणालीगत जोखिमों को कम किया जा सके। एफएसबी ने जी-20 के नेताओं को अप्रैल 2012 में प्रस्तुत की गई शैडो बैंकिंग संबंधी अपनी रिपोर्ट में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की है और इस बात का उल्लेख किया है कि नीति संबंधी अन्य सिफारिशें 2012 के अंत तक की जाएंगी।

समाधान व्यवस्था तथा बेल-इन की पद्धति

2.37 वैश्विक वित्तीय संकट ने समाधान व्यवस्था में सुधार करने की भारी जरूरत को रेखांकित किया है ताकि संबंधित प्राधिकारी विफल हो रही वित्तीय संस्थाओं का समाधान वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता पैदा किए बिना अथवा दिवालिया होने की स्थिति में समर्थन देने के कारण होने वाली हानि के लिए करदाताओं को जोखिम में डाले बिना कर सकें। अमरीकी सरकार के डॉड-फ्रैंक अधिनियम ने बड़ी तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंक संस्थाओं एवं वित्तीय संस्थाओं की विफलता से निपटने के लिए फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन के प्राधिकार को बढ़ा दिया है। उसी प्रकार यूके की सरकार ने विशेष समाधान व्यवस्था एवं विशेष प्रशासन व्यवस्था को कार्यान्वित किया है ताकि बैंकों तथा निवेश फर्मों का समुचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यूरोपियन कमीशन ने भी यूरोपियन यूनियन-व्यापी संकट प्रबंधन एवं बैंक समाधान फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए प्रस्ताव जारी कर दिया है ताकि समाधान के उपायों एवं राष्ट्रीय प्राधिकारियों के दृष्टिकोण में समानता लाई जा सके।

2.38 एफएसबी ने नवंबर 2011 में प्रभावी समाधान व्यवस्था संबंधी मानक जारी कर दिए हैं। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (गैर-बैंकों सहित) की समस्याओं के समाधान के लिए देशों के पास व्यापक अधिकारों के साथ समाधान प्राधिकारियों का होना जरूरी है ताकि देशों के बीच सहयोग में आनेवाली बाधाओं को कम किया जा सके तथा कम-से-कम वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण के रूप में चिह्नित बैंकिंग समूह के लिए बहाली तथा समाधान योजनाएं एवं प्रबंधन समूहों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

2.39 एफएसबी प्रमुख मानदंडों को बेंचमार्क के रूप में लेकर अपने सदस्य देशों की वर्तमान समाधान व्यवस्था का मूल्यांकन करने एवं इन व्यवस्थाओं में किसी नियोजित परिवर्तन पर विचार करने के लिए पहली समकक्ष समीक्षा कर रहा है।

2.40 विनियामक सुधार के अजेंडे में प्रगति हुई है, परंतु कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तथा कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। परंतु इसका पूर्ण कार्यान्वयन सुदृढ़ राजनैतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा क्योंकि देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा स्वयं के एवं मूल देशों में वित्तीय समूहों के लिए समाधान संबंधी अधिकारों की सीमा एवं गुंजाइश को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कानून बनाने की जरूरत होगी।

6. समग्र मूल्यांकन

2.41 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली ने 2011 तथा 2012 में अब तक कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे - कमजोर पड़ती वैश्विक वृद्धि तथा विशेष रूप से यूरोपीय बैंकों में सरकारी ऋण संकट का बढ़ना एवं इससे संबंधित निधीयन एवं डीलीवरेजिंग का जोखिम। इने चुनौतियों के वर्ष 2013 में भी बने रहने की संभावना है क्योंकि गिरावट का जोखिम बरकरार है, बशर्ते उन्नत देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा उठाये गए कदमों से वृद्धि में सुधार हो। चुनौतियों से निपटने के लिए जो राजकोषीय मितव्ययिता के उपाय किए गए हैं उनसे भी उन्नत देशों की वृद्धि तथा रोजगार संबंधी संभावनाएं कमजोर पड़ेंगी। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बैंक निधीयन के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर सीमित निर्भरता के चलते बेहतर स्थिति में हैं, परंतु यदि यूरो क्षेत्र का सरकारी ऋण संकट जारी रहता है तो वे भी गिरावट संबंधी जोखिम का सामना करेंगे, जैसे-व्यापार वित्त की उपलब्धता में कमी, जोखिम उठाने की इच्छा में गिरावट, पूंजी का बाहर जाना एवं विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव।

2.42 हाल की अवधि में उन्नत देशों ने आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए मौद्रिक सहायता उपायों का सहारा लिया। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने वित्तीय सहायता III की घोषणा की जो प्रतिमाह 40 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त एजेंसी बंधक समर्थित प्रतिभूतियों की खरीद का एक व्यापक उपाय है। ईसीबी ने यूरोप

के सरकारी ऋण संकट संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए यूरो क्षेत्र के सरकारी बांडों को द्वितीयक बाजार से खरीदने के लिए “निष्प्रभावित” एकमुश्त मौद्रिक लेनदेन (ओएमटी) कार्यक्रम की घोषणा की। बैंक ऑफ जापान ने भी आस्ति खरीद कार्यक्रम के कुल आकार में लगभग 21 ट्रिलियन येन की वृद्धि करके कुल लगभग 91 ट्रिलियन येन कर दिया। इन उपायों ने यूरोपीय यूनियन के बैंकों के निधीयन संबंधी दबावों तथा वित्तीय तनाव को कम किया। “यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था” के रूप में 500 बिलियन यूरो के स्थायी बचाव पैकेज की शुरुआत किये जाने तथा ईसीबी

के अंतर्गत एकल बैंकिंग विनियामक की स्थापना के प्रस्ताव ने भी वित्तीय बाजार के दबाव को कम करने में मदद की।

2.43 आगे चलकर कमजोर वैश्विक वृद्धि तथा आकार ले रहे नए विनियामक परिवेश के चलते बैंकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इससे कारोबार करने की लागत में बढ़ोतरी होगी जिससे उनकी लाभप्रदता में कमी आएगी। दीर्घावधि में वैश्विक बैंकों को लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास की बहाली की दिशा में कार्य करना चाहिए।